



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 26 दिसम्बर, 2000/5 पौष, 1922

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 26 दिसम्बर, 2000

संख्या 1-74/2000-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का

विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-आधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-,
(अजय भण्डारी),
सचिव।

2000 का विधेयक संख्यांक 20

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2000 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह 15 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, — धारा 2 का संशोधन ।

(क) खण्ड 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(13-क) “कुटुम्ब” से, एक ही पूर्वज से अवजनित, दत्तक ग्रहण सहित, सभी सदस्यों का अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है जो ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में यथा दर्शित, स्थायी रूप में एक साथ निवास, पूजा तथा भोजन करता है ; और

(ख) खण्ड (46) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(46-क) “वार्ड” से, अधिनियम की धारा 124 के अधीन यथा अवधारित, पंचायत क्षेत्र में एक-सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र, अभिप्रेत है ;” ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

धारा 5 का संशोधन ।

(क) उप-धारा (1) में,

(i) “प्रति वर्ष दो साधारण बैठकें करेगी, एक ग्रीष्म ऋतु में और दूसरी शीत ऋतु में” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर, “प्रतिवर्ष चार साधारण बैठकें करेगी, और प्रत्येक बैठक वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर मास के प्रथम रविवार को होगी,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ,

(ii) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ; और

(ख) उप-धारा (3) में, —

- (i) "इसके कुल सदस्यों की संख्या का पांचवां भाग होगी," शब्दों के स्थान पर, "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई," शब्द रखे जाएंगे ; और
- (ii) परन्तु क में, "इसके सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दसवां भाग," शब्दों के स्थान पर "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवां भाग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 7-क
का अन्तः-
स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7-क. उप-ग्राम सभा का गठन:—

- (1) ग्राम सभा के प्रत्येक वार्ड के लिए उप-ग्राम सभा होगी ।
- (2) वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम सभा के सभी सदस्य, उप-ग्राम सभा के सदस्य होंगे ।
- (3) प्रत्येक उप-ग्राम सभा, प्रतिवर्ष दो साधारण बैठकें बुलाएगी और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य का होगा । उप-ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा की जाएगी, जो कार्यवाहियों को भी अभिलिखित करेगा ।
- (4) उप-ग्राम सभा की बैठकों का समय और स्थान, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा नियत और अधिसूचित किया जाएगा ।
- (5) उप-ग्राम सभा, ग्राम सभा की साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सदस्यों को नाम निर्देशित करेगी और वह सदस्य ऐसी रीति से नाम निर्देशित किए जाएंगे जिसमें वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले कुल कुटुम्बों का 15 प्रतिशत नाम निर्दिष्ट किया जाएगा बशर्ते कि नाम निर्देशनों का एक तिहाई महिलाओं से होगा :

परन्तु यह नाम निर्देशन ग्राम सभा के किसी सदस्य को, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने से विवर्जित नहीं करेगी ।

- (6) उप-ग्राम सभा, अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विवाधकों पर विचार कर सकेगी और ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा को सिफारिशें कर सकेगी ।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 में, खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 13 का संशोधन ।

“(न) लोक सम्पत्ति जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक मड़क पर मील पत्थरों, पथों, सिचाई एवं पूति स्कीमों, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक कुओं, बम्बों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला-मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य/पशुपालन/आयुर्वेदिक संस्थान भवनों का संरक्षण ।” ।

6. मूल अधिनियम की धारा 110 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तु जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

धारा 110 का संशोधन ।

“परन्तु यह कि यदि उधार, आय बढ़ाने वाली परिसम्पत्तियों के लिए लिया जाना है और परियोजना, उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक विनीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित की गई है, तो उधार लेने के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं होगी । तथापि परियोजना, जिसमें परियोजना की विशिष्टियां अंतर्बलित होंगी के व्यौरों के बारे में सरकार को सूचित करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत को, उधार लेने के लिए, ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा ।” ।

7. मूल अधिनियम की धारा 131 में, उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 131 का संशोधन ।

“(6) पंचायत में, उस विस्तार तक आकस्मिक रिक्तियां घटित होने की दशा में, कि पंचायत की बैठक बुलाने के लिए शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति पूर्ण नहीं करती है, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, तब तक जब तक इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार नए सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं पंचायत में घटित आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

परन्तु राज्य सरकार विशिष्ट आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए केवल, उसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किया जाने और उस विशिष्ट पंचायत का पद धारण करने के लिए पात्र है ।” ।

8. मूल अधिनियम की धारा 138 में, उप-धारा (2) में, शब्द और चिन्ह “की पुष्टि कर सकेगी, उसे,” के स्थान पर शब्द “को” रखा जाएगा ।

धारा 138 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 184 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

धारा 184 का प्रतिस्थापन ।

“184 विकास योजनाएं तैयार करना—

(1) प्रत्येक पंचायत, अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कृत्य तथा ऐसे अन्य कृत्य की, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं जहां तक

उनके अपने-अपने क्षेत्र के भीतर ऐसे कृत्यों के अनुपालन करने हेतु, पंचायत निधियां अनुज्ञात करती हैं, प्रतिवर्ष विकास योजना तैयार करेगी ।

- (2) प्रत्येक पंचायत, प्रति वर्ष अपने-अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए, विकास योजना की स्कीमें तैयार करेगी और इस अधिनियम के अधीन गठित की गई जिला योजना समिति को प्रेषित करेगी ।” ।

धारा 185
का संशो-
धन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 185 में,—

- (क) उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (क) को, खण्ड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और ऐसे पुनः संख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड (क) अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) राज्य सरकार द्वारा चयन किया जाने वाला मन्त्री, जो जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी होगा ;”, और

(ख) उप-धारा (5) का लोप किया जाएगा ।

2000 के
अध्यादेश
संख्यांक-1
का निरसन
और व्या-
वृत्तियां ।

11. (1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की हुई या की गई समझी जाएगी जैसे कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात की गई हो या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 जो 23 अप्रैल, 1994 को अधिनियमित किया गया था, इसके कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयाँ ध्यान में आई हैं। कठिनाइयों को दूर करने हेतु अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं :—

1. पदों "कुटुम्ब" और "वार्ड" को परिभाषित किया जाना अपेक्षित है।

2. यह देखा गया है कि ग्राम सभा में साधारणतया गणपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है। इसका एक कारण यह है कि ग्राम सभा के सदस्यों को ग्राम सभा की बैठकों की सूचना का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए प्रस्तावित है कि बैठक का दिन अधिनियम में ही नियत हो, किसी भी विकासात्मक क्रियाकलाप में लघुतम और अत्यन्त महत्व की इकाई कुटुम्ब है। किसी भी ग्राम सभा में अधिकतम कुटुम्बों का प्रतिनिधित्व महत्व का है, इसलिए, ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति की कसौटी में परिवर्तन लाया जा रहा है ताकि कुटुम्बों के प्रतिनिधित्व को, इसके किसी भी सदस्य के उसके बैठक में भाग लेने के अधिकारों में विघ्न डाले बिना, सुनिश्चित किया जा सके।

3. ग्राम सभा एक बड़ा निकाय है जहाँ पर कतिपय विषयों पर, छोटे ग्रुपों में, बेहतर चर्चा की जा सकती है। इसलिए विकास की प्रक्रिया में लोगों का अधिकांश मात्रा में सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा के प्रत्येक वार्ड के लिए उप-ग्राम सभा का गठन किया जाना अपेक्षित है।

4. साधारणतया यह देखा गया है कि सार्वजनिक सम्पत्ति जैसे कि सूचना पट्टों, सार्वजनिक मार्ग पर मील पथरों, रास्तों, सिंचाई और जलापूर्ति स्कीमों, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक कुओं, बम्बों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों, पाठशाला भवनों, चिकित्सा/पशु चिकित्सा/आयुर्वेदिक संस्थान भवनों को विकृत या नष्ट किया जाता है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों को ऐसी सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए साधारण आदेश करने के लिए सशक्त बनाया जाए।

5. पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता देने के लिए पंचायतों द्वारा ऋण लेने हेतु सरकार की पूर्व मंजूरी की शर्त को अधिव्यक्त किया जाए, यदि परियोजनाओं को आर्थिक रूप से/वित्तीय रूप से ऋणदाता संस्थानों द्वारा व्यवहार्य निर्धारित किया गया हो।

6. सदस्यों की मृत्यु, पद त्याग, निलम्बन और हटाए जाने या किसी अन्य कारण द्वारा आकस्मिक रिक्तियाँ होने पर और अपेक्षित गणपूर्ति पूर्ण न होने के कारण पंचायत के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में, व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार या विधि प्राधिकारी को, सम्बन्ध पंचायत से, आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए व्यक्तियों को तब तक नामांकित करने के लिए सशक्त करने हेतु प्रस्ताव किया जाता है जब तक कि अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंचायत के नए सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते।

7. अधिनियम की धारा 138 के विद्यमान उपबन्धों के अधीन पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव, दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा, या उसके द्वारा किए गए किसी कृत्य को प्रतिषिद्ध करने वाला विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की राज्य सरकार द्वारा पुष्टि की जानी अपेक्षित है। अनावश्यक विलम्ब का परिवर्तन करने के लिए प्रस्तावित है कि पुष्टि के उपबन्ध का लोप किया जाए।

8. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि पंचायती राज संस्थाएं, समस्त तीन स्तरों पर, स्वशासन की स्वतन्त्र संस्थाएं हैं, और जिला योजना समिति को स्थापित करने से, पंचायतों को सभी तीन स्तरों

पर उनके अपने-अपने क्षेत्र के भीतर विकास योजना तैयार करने के लिए सशक्त करना आवश्यक होगा।

9. जिला योजना समिति को योजना बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और इसके लिए सभी दावेदारों से संरचना और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिला योजना समिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि राज्य सरकार को जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में, मन्त्री को चुनने के लिए, सशक्त किया जाए और जो इसका अध्यक्ष भी होगा ऐसा करना न केवल सभी अभिकरणों के अच्छे आवेष्टन में सहायक होगा अपितु राज्य सरकार के साथ अधिक अच्छे समन्वयन और आसान कार्यान्वयन में भी सहायक होगा।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 को संशोधित किया जाना अति-आवश्यक था, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का 1) को 13 नवम्बर, 2000 प्रख्यापित कर दिया है और उसे हिमाचल प्रदेश में तारीख 15 नवम्बर, 2000 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को आंशिक उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रकाश चौधरी,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
..... 2000.

वित्तीय जापन

इस विधेयक के उपबन्धों को विद्यमान तंत्र द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 20 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) BILL, 2000

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2000.

Short title and commencement.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 15th day of November, 2000.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

Amendment of section 2.

(a) after clause (13), the following shall be added, namely:—

“(13-A) “family” means a joint family of all persons descended from common ancestor including adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the parivar register of the Gram Panchayat;” and

(b) after clause (46), the following shall be added, namely:—

“(46-A) “ward” means a single member territorial constituency in a Panchayat area as determined under section 124 of the Act;”.

3. In section 5 of the principal Act,—

Amendment of section 5.

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words and sign “two general meetings in each year, one in the summer and the other in the winter”, the words “four general meetings in each year and every meeting shall be held on the first Sunday of January, April, July and October” shall be substituted ;

(ii) first proviso shall be deleted; and

(b) in sub-section (3), —

(i) for the words “one-fifth of the total number of its members”, the words “representation of at least one-third of the total

number of families represented by one or more members of the Gram Sabha" shall be substituted; and

- (ii) in proviso, for the words "atleast one-tenth of the total number of its members", the words "representation of at least one-fifth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha" shall be substituted.

Insertion
of section
7-A.

4. After section 7 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

- "7-A. Constitution of the Up-Gram Sabha.**—(1) There shall be a Up-Gram Sabha for each ward of a Gram Sabha.
- (2) All members of the Gram Sabha residing within the area of the ward shall be members of the Up-Gram Sabha.
- (3) Every Up-Gram Sabha shall hold two general meetings in each year, and it shall be the responsibility of the member of the Gram Panchayat representing the ward to convene such meetings. The meeting of the Up-Gram Sabha shall be presided over by the member of the Gram Panchayat representing the ward, who shall also record the proceedings.
- (4) The time and place of the meetings of the Up-Gram Sabha shall be fixed and notified by the member of the Gram Panchayat representing the ward.
- (5) The Up-Gram Sabha shall nominate its members to represent it in the general meeting of the Gram Sabha and these members shall be nominated in a manner so that 15% of the total families residing in the area of the ward get nominated provided that one-third of the nominations shall be of women :

Provided that this nomination shall not debar any member of Up-Gram Sabha from attending the general meetings of the Gram Sabha.

- (6) The Up-Gram Sabha may deliberate on issues relating to its area and make recommendations to the Gram Panchayat or Gram Sabha."

Amendment
of section 13.

5. In section 13 of the principal Act, after clause(s), the following shall be added, namely:—

- "(t) protect public property such as sign boards, mile-stones on public roads, paths, irrigation and water supply schemes, public taps, public wells, hand pumps, community centres, mahila mandal bhawans, School buildings, Health/Veterinary/Ayurvedic Institution buildings."

Amendment
of section
110.

6. In section 110 of the principal Act, the following provisos shall be added, namely:—

- "Provided that if loan is to be raised for creation of income generating assets and the project is assessed by the lending institution as economically/financially viable, previous sanction of the State

Government shall not be essential for taking a loan. It shall, however, be mandatory to inform the Government about the details of the project which will include the particulars of the project :

Provided further that the Gram Panchayat shall be required to obtain prior approval of the Gram Sabha for raising a loan.”.

7. In section 131 of the principal Act, after sub-section (5), the following shall be added, namely :—

Amendment
of section
131.

“(6) In the event of occurrence of casual vacancies in a panchayat to the extent that the number of the remaining elected office bearers do not fulfil the quorum required for convening a meeting of the Panchayat then the State Government or the prescribed authority may nominate persons to fill the casual vacancies occurred in a Panchayat till new members are elected in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder :

Provided that the State Government will nominate only that person to fill a particular casual vacancy who is eligible to be elected as an office bearer of a Panchayat and to hold office of that particular Panchayat in accordance with the provisions of this Act.”.

8. In section 138 of the principal Act, in sub-section (2), the word “confirm” shall be omitted.

Amendment
of section
138.

9. For section 184 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution
of section
184.

“184. **Preparation of Development Plans.**—(1) Every Panchayat shall prepare every year a development plan to perform functions specified in Schedule-I and Schedule-II and such other functions as may be specified by the State Government, in so far as the Panchayat funds allow to perform such functions within its respective area.

(2) Every Panchayat shall prepare every year a development plan of schemes for economic development and social justice for their respective area and submit it to the District Planning Committee constituted under this Act.”.

10. In section 185 of the principal Act, —

(a) in sub-section (2), the existing clause (a) shall be re-numbered as clause (aa) and before clause (aa) so re-numbered, the following clause (a), shall be inserted, namely :—

Amendment
of section
185.

“(a) A Minister to be chosen by the State Government who shall also be the Chairperson of the District Planning Committee;” ; and

(b) sub-section (5) shall be omitted.

11. (1) The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2000 (1 of 2000) is hereby repealed.

Repeal of
Ordinance
No. 1 of
2000 and
savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the repealed Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the implementation of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 certain practical difficulties have been noticed. In order to overcome the difficulties, the following amendments are required to be brought in the Act:—

1. The expressions "family" and "ward" are required to be defined.
2. The information about meetings of Gram Sabha is not known to the Gram Sabha members. Therefore, it is proposed to fix the day of the meeting in the Act itself. It has been seen that the quorum in the Gram Sabha is not generally available. The smallest and the most important unit in any developmental activity is a family. Representation of maximum number of families in a Gram Sabha is important, therefore, the criteria for quorum of the meeting of the Gram Sabha is being changed to ensure representation of families without disturbing the rights of any member to participate in the meeting.
3. The Gram Sabha is a big body, whereas, certain issues can be better discussed in smaller groups. Therefore, in order to ensure participation of people at large in the process of development, Up-Gram Sabha for each ward of Gram Sabha is required to be constituted.
4. It has been generally noticed that the public property such as sign boards, mile stones on public roads, paths, irrigation and water supply schemes, public taps, public wells, hand pumps, community centres, mahila mandal bhawans, School buildings, Health/Veterinary/ Ayurvedic Institutions buildings are defaced or destroyed. As such, it is proposed that the Gram Panchayats may be empowered to make general orders to protect such public property.
5. In order to give more autonomy to the Panchayati Raj Institutions the condition of previous sanction of the State Government for raising of loans by Panchayats may be waved off if, projects have been assessed as economically/financially viable by the lending institutions.
6. Practical difficulties are being faced in the day to day functioning of a Panchayat, where the casual vacancies of members occur due to death, resignation, suspension and removal or for any other reason and the required quorum is not complete. As such it is proposed to empower the State Government or the prescribed authority to nominate persons to fill the casual vacancies in the Panchayat concerned, till new members of the Panchayat are elected under the provisions of the Act.
7. Under the existing provisions of section 138 of the Act, every order of the prescribed authority regarding suspension of execution of the resolution passed, license or permission granted or prohibiting the performance of any act by a Panchayat is required to be confirmed by the State Government. In order to avoid unnecessary delay, it is proposed that the provision of confirmation may be deleted.
8. With a view to ensure that the Panchayati Raj institutions at all the three levels are independent institutions of self governance, and with the setting up of the District Planning Committee it would be important to empower the Panchayats at all the three levels to prepare development plan within their respective areas.
9. District Planning Committee has to play a very important role in planning and therefore must have a structure and representation from all the stake holders. Considering the importance of District Planning Committee, it has been proposed that the State Government may be empowered to choose the Minister to be the member of the District Planning Committee and who shall also be its chairperson, which would

not only help in better involvement of all agencies but would also help in better co-ordination with the State Government and easy implementation.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 had to be amended urgently, the Governor, Himachal Pradesh, under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2000 (Ordinance No. 1 of 2000) on the 13th day of November, 2000 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 15th November, 2000. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with minor modifications.

PARKASH CHAUDHARY,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ———— December, 2000.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of this Bill shall be implemented by the existing machinery and there shall be no additional expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

